

not able to give that figure, for which I will require notice. It will produce urea to the extent of 154,000 tonnes per annum. This will materialise by August this year. Then, we have the carbonisation and briquetting plant which, again, will depend for its production on the market that has been created for the new product, which is called 'Le.o' and it will take some time.

**SHRI ARJUN ARORA :** With regard to the loss suffered by this Corporation the Minister has said that the losses were inevitable. May I know why they were inevitable? The Deputy Minister has said that the complex will begin to make profits when it is completed. Certain parts of the complex have already been completed. May I know whether they are likely to make any profit as a result of the completion of the whole project, because a complex consisting of several units will remain so and each unit will have to make a profit? May I know what action the Government is taking and what efforts have been made to make each unit profitable? Or, is the Government waiting for the complex to be completed and then expects that the mere magic of completion will produce profits?

**SHRI S. K. DEY :** There can be no room for magic in a commercial enterprise.

**SHRI ARJUN ARORA :** But you seem to believe in that.

**SHRI S. K. DEY :** I do not. I have already indicated that when production begins at full capacity there will be full utilisation of the capital assets and capital equipment and also the staff who inevitably to be on the pay rolls of the undertaking. I would say that the power house is already making a profit. The fertiliser plant will also begin to make a profit this year, because it will have come into full production by August, as I have mentioned. The lignite mine also will have begun to earn profit. It will have begun to give full production once the power house has been installed to full capacity and also the fertilisers plant.

#### FACILITIES FOR THIRD CLASS PASSENGERS

\*931. **SHRI JAGAT NARAIN :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether certain decisions have been taken to give more facilities to the third class passengers; and

(b) what steps are proposed to be taken to overcome over-crowding in third class coaches?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) :** (a) The policy is to provide as many facilities as feasible to third class passengers commensurate with the financial implications.

(b) Additional trains are being introduced besides extending runs of existing services and augmentation of their loads. In addition, special trains are also run to clear seasonal rush of traffic.

**श्री जगत नारायण :** क्या वजीर साहब बतलायेंगे कि थर्ड क्लास के पैसेंजर्स की एमिनिटीज के लिए वे इस साल में कितना रुपया खर्च कर रहे हैं और पिछले साल में कितना खर्च किया था।

**डा० राम सुभग सिंह :** इसमें पिछले साल 4 करोड़ की व्यवस्था थी यात्रियों की सुविधा के लिए। यह पूरा खर्च नहीं हो पाया। थोड़ा शेष रह गया, लेकिन इस साल 4 करोड़ के करीब जरूर खर्च किया जाएगा।

**श्री जगत नारायण :** क्या वजीर साहब बतलायेंगे कि पिछले साल 27 करोड़ रुपए का पैसेंजर्स की अमिनिटीज के लिए फैसला किया गया था? इसमें 4 करोड़ ही रखा और वह भी खर्च नहीं हुआ। क्या यह ठीक है कि इस साल 22 करोड़ रुपया उससे कम कर दिया गया है पैसेंजर्स की अमिनिटीज के लिए।

**डा० राम सुभग सिंह :** पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए पहले 3 करोड़ सालाना रहता था। पिछले साल 4 करोड़ किया गया, लेकिन अब इसको कम करने का इरादा नहीं है। इसको जरूर खर्च किया जाएगा। कई एक कारण होते हैं जिससे खर्च करना कुछ कठिन हो जाता है।

**श्री बाबा साहेब सावनेकर :** क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकूंगा कि थर्ड क्लास पैसेजर्स को मेल में बैठने में सुविधा देने के लिए स्टेशन स्टाफ से कहा गया है? अक्सर यह देखते हैं कि थर्ड क्लास में जो जबरदस्त है, जैसा कि मिसाल है 'जिसकी लाठी उसकी भैंस', वह अन्दर घुस जाता है। पठानकोट और पंजाब मेल मनमाड से चलकर जलगांव और चालीस गांव पर थोड़ा टाइम रुकती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां इनफार्मेशन भेज दी जाए कि इस डिब्बे में जगह है, यहां बिठाओ। थर्ड क्लास के पैसजर्स जगह न मिलने के कारण इधर-उधर भागते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे स्टेशन स्टाफ से

**श्री सभापति :** प्रार्थना का मौका नहीं है, प्रश्न करिए।

**श्री बाबा साहेब सावनेकर :** वे स्टेशन स्टाफ को कहें कि पैसेजर्स को जगह दिलाएं।

**डा० राम सुभग सिंह :** प्रति दिन इसकी व्यवस्था करने की, इसमें उन्नति करने की कोशिश की जा रही है कि तृतीय दर्जे के मुसाफिरो को सुविधायें मिलें और इसी से इतनी ज्यादा गाड़िया भी बढ़ाई जा रही हैं, 1965-66 में 175 के करीब गाड़ियां बढ़ाई गईं और इसी सीजन (अप्रैल 1966 समय सारणी) में 53 गाड़िया बढ़ाई गईं, डिब्बे भी बढ़ाये गये ताकि उनको असुविधा न हो।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति जी, पहले दर्जे में जितनी जगह होती है उतने ही मुसाफिरो को बैठने या सोने के टिकट दिये जाते हैं, यही नियम तीसरे दर्जे पर लागू क्यों नहीं होता। सरकार प्रथम श्रेणी के यात्रा और तीसरे दर्जे के यात्री में यह भेद कब तक करती रहेगी। सरकार यह प्रबन्ध क्यों नहीं करती कि तीसरे दर्जे में जितने यात्रियों के बैठने की जगह है उतने ही टिकट दिये जायें।

**डा० राम सुभग सिंह :** सिद्धांततः यह बात बिल्कुल स्वीकार्य है लेकिन जिस दिन भी या अगर आज हम लोग ऐसा करना चाहें कि थर्ड क्लास के उतने ही टिकट ईश्यू करें हर एक स्टेशन पर जितनी कि जगह हो तो उससे जो फायदे हैं उनकी तुलना में तीसरे दर्जे के उन मुसाफिरो को जिनको टिकट नहीं मिलेगा और स्टेशन पर आ चुके होंगे उनकी कठिनाइयों का अगर माननीय प्रश्नकर्ता महोदय अंदाजा लगायेंगे तो यह समझेंगे कि यह बात अभी व्यावहारिक नहीं है।

**श्री राजनारायण :** क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि 'आज' शब्द के क्या माने हैं। 18 साल कांग्रेस राज को, शासन को, हो गये लेकिन यह "आज" कब तक इस्तेमाल होता रहेगा।

**डा० राम सुभग सिंह :** श्रीमान्, मेरे अत्यंत नज़दीकी माननीय मित्र का दल भी केरल में एक बार शासन करने गया था और उस वक्त जो व्यवस्था उन्होंने अच्छी करने की और उसका परिणाम यह हुआ कि आज न वह ही है और न दूसरे हैं और कांग्रेस ज्यों की त्यों 18 वर्ष से है, और रोज-रोज़ इनकी सुविधा बढ़ रही है।

**श्री राजनारायण :** श्रीमान्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। अगर मंत्री लोग ऐसा जवाब देने लगेंगे तो सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ेगी। हम पूछ रहे हैं कि क्या सरकार कोई निश्चित समय बाधेगी, कितने समय के अन्दर, तृतीय श्रेणी में यात्रा करने वाले मुसाफिरो को पूरी सुविधा हो जाएगी और जितने टिकट बेचे जाते हैं उतनी उनको जगह मिल जाएगी। इस पर हमें केरल का उदाहरण मंत्री महोदय देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के उत्तर देने से भविष्य में उनको रोकें और हमारे प्रश्न का सीधा उत्तर वह दें।

**श्री सभापति :** आपने सवाल भी शाय-राना किया था, आपने प्रश्न यह किया था कि "आज" कब तक रहेगा।

श्री राजनारायण : मैंने प्रश्न यह किया था कि आज के माने क्या हैं, सरकार निश्चित हमें बताए कि वह कितना समय लेना चाहती है।

श्री सभापति : यह आप फर्माते तो वह जवाब देते।

श्री राजनारायण : अब दे।

डा० राम सुभग सिंह श्रीमान्, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगो का लक्ष्य यही है कि जितने तीसरे दर्जे के मुसाफिर हैं उनको जगह मिले। इस बात का ध्यान किया जाता है कितने यात्री होंगे, अभी साल में दो हजार करोड़ यात्री रेल से टिकट खरीद कर यात्रा करते हैं और कतिपय ऐसे होंगे जो नहीं भी खरीदते हैं, तो दो हजार करोड़ में कितनी वृद्धि होगी इसका अंदाजा लगाया जाता है। बजट आपके सामने आता है, अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूरी, कुछ कठिनाइयों के चलते शुरू नहीं हो पाई है, तो हमारी सीमाये हैं, हमारे आर्थिक सीमाएं हैं उनको लिहाज में रखते हुये जितनी सुविधायें बढ़ा सकते हैं वह बढ़ाई जाएगी। मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं उनको किसी तरह से तबलीफ पहुँचाऊँ, चूँकि उन्होंने कांग्रेस के 18 वर्ष के शासन की चर्चा की थी इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने मित्र को जवाब दूँ।

SHRI F. V. ANANDAN : Is it not a fact that prior to independence only about 30 crores of people used the trains in this country, annually and today 200 crores of people use the trains in this country although the train services have increased from 3 000 to 10,000 today? What proposals has the Minister yet got to solve this problem of over-crowding?

DR. RAM SUBHAG SINGH : Therefore, I said what the hon. Member has said that the number has phenomenally increased during the post-independence period, the number of passengers, and regarding facilities the Railways have developed their capacity so remarkably which I do not however consider as adequate enough to meet the demand of today, but the increase has been phenomenal both for carrying

goods as well as passenger traffic. Therefore, we are virtually daily increasing the number of trains and coaches.

श्री गोडे मुराहरि : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सही नहीं है कि हर साल रेलवे बजट तो सरप्लस होता जाता है फिर भी क्या दिक्कत पड़ती है कांग्रेस सरकार को सुविधा देने में।

डा० राम सुभग सिंह : असल में जो पजी लगती है उसके लिये माननीय सदस्य महोदय जानते होंगे कि एक कवेशन कमेटी है जो कि पार्लियामेंट की सम्मानित कमेटी है, उसकी सिफारिशों के आधार पर सेटल फंड में देना पड़ेगा, फिर अमेनिटीज के लिये, स्टाफ के लिए, डीयरनेस वगैरह के लिये वृद्धि होती है, तो इन सब चीजों को देख कर करना पड़ता है। अगर कोई काम एक दृष्टि से ही देखें, एक तरफ ही विस्तार करने की कोशिश करे तो यह सम्भव नहीं होता, हालाँकि हम लोगों की सहानुभूति पूरी है और कोशिश करेंगे कि तृतीय श्रेणी के मुसाफिरों को जितनी सुविधा चाहिये उतनी उपलब्ध की जाए, उसमें रेल मंत्रालय किसी से किसी मात्रा में पीछे नहीं रहेगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : क्या श्रीमान् यह बतायेंगे कि जिन-जिन क्षेत्रों में ओवरक्राउडिंग होती है इसकी कोई सर्वे करके कोई रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इसके साथ ही इस रिपोर्ट को भविष्य में जब तक कार्यान्वित की जा सके इसकी सम्भावनाओं को देखते हुये कोई ऐसा फेज्ड प्रोग्राम बनाया है कि अमुक-अमुक क्षेत्र में इस-इस साल में इतना-इतनी गाड़ियाँ बढ़ाई जायें और अगर ऐसा है तो क्या उसे टेबिल पर रखने का कष्ट करेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : इसके अध्ययन के लिये एक सैल है जो कि अध्ययन करता है। जहाँ तक ओवरक्राउडिंग का, भीड़ का, प्रश्न है, सन् 1955 ई० से 1964 ई० तक जो आकड़े हैं, परसेटेज हैं वह बराबर कम होते जाते हैं और जहाँ-जहाँ ज्यादा परसेटेज है

बहा-बहा ज्यादा ट्रेन इट्रोड्युज की जाती है, ज्यादा कोचेंज बढ़ाई जाती हैं। जो पांच वर्षों के आकड़े हैं वह मैं टेबिल पर रख दूंगा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री राम सहाय मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने इस बात की जांच की है कि ओवर-क्राउडिंग की वजह से प्रति स्टेशन पर कितने टिकट वापस होते हैं।

डा० राम सुभग सिंह इसके सही आंकड़े तो मैं बाद में दे सकूंगा, इसका नोटिस नहीं था, प्रति स्टेशन का बताना तो अभी सम्भव नहीं है।

श्री राजनारायण : क्या सरकार . . .

श्री सभापति : हमारा दायित्व यह है कि जिन साहब के नाम पर सवाल न हो वह एक स्पष्टीकरण करते हैं। फिर भी आप दूसरा करना चाहते हैं तो कीजिये।

श्री राजनारायण : विनम्रता के साथ निवेदन है कि किसी बात को साफ करने के लिये ज्यादा सवाल करने की जरूरत महसूस हो तो उनको ज्यादा मौका दिया जाया करे।

मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या सरकार उन दिक्कतों को पेश करेगी कि अब तक क्यों नहीं सब क्लासों को तोड़ कर एक क्लास बना दिया गया, ऐसी कार्यवाही करने में सरकार को क्या दिक्कत है।

डा० राम सुभग सिंह अभी यह सम्भव नहीं है क्योंकि मैं अत्यंत विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि माननीय प्रश्नकर्ता महोदय भी चाहते हैं कि उनको सहूलियत मिले फर्स्ट क्लास में चलने की। हमारे पास इन्होंने भी चिट्ठ लिखी है। तो यह व्यावहारिक नहीं है। रात में तीसरे दर्जे में भी जो तीसरे दर्जे का मुसाफिर है वह सोना चाहेगा सरकार कितनी भी आयडियल, कितनी भी आदर्श व्यवस्था करे लेकिन वहां पर सोने और बैठने की जगह रखनी ही पड़ेगी।

श्री गोडे मुराहरि यह गलतबयानी कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि चिट्ठ लिखी है कि हम फर्स्ट क्लास की सुविधा चाहते हैं, मगर वह बिल्कुल गलतबयानी करते हैं, झूठ कहते हैं, हममें से कोई यह नहीं चाहता।

श्री सभापति श्री मुराहरि, आपने जो लफ्ज "झूठ" का बोला है यह पार्लियामेंटरी नहीं है। इसे आप वापस ले लें।

श्री गोडे मुराहरि अच्छा, असत्य या गलत मान लीजिये, निराधार कह दें। लेकिन है वैसा ही।

श्री राजनारायण श्रीमान्, पर्सनल एक्स-प्लेनेशन

MR CHAIRMAN : It is not necessary

श्री राजनारायण जरा मेरा निवेदन सुन लीजिये। मेरे ऊपर मंत्री जी ने स्पष्ट आक्षेप किया है कि मैंने उनको पत्र दिया है कि हमको फर्स्ट क्लास की सुविधा दी जाए। यह बिल्कुल गलत है, असत्य है, निराधार है और मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से सवाल का जवाब मंत्री महोदय देंगे तो आप स्वतः सोचें कि इस सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से कैसे चल पायेगी। हमने उनको अनेक पत्र लिखे हैं कि यह गड़बड़ी है, यह दिक्कत है, यह परेशानी है इसका दूर कीजिये।

DR B. N. ANTANI : Is the hon. Minister aware that passengers from Kandla to Northern India, Rajasthan and Delhi have to have a compulsory halt of seven hours at Palanpur before getting connections? Has the Minister got any representations from Kandla and what steps are being taken to see that such delays and halts are avoided? The Minister may be aware that in order to develop trade from Rajasthan and Northern India to Kandla this sort of delay is one of the reasons discouraging traffic?

DR RAM SUBHAG SINGH We received such a representation and we have done our best to meet some of the points though it has not been possible to meet all the points in the representation. And I might be permitted to say that this is not

coming within the purview of this question so that a detailed reply can be given.

#### SUPPLY OF UNIFORMS TO STAFF OF CENTRAL RAILWAY

\*932. SHRI D. THENGARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state—

(a) whether majority of staff on Central Railway have not been supplied uniforms for some years; and

(b) when the staff on the Central Railway will be supplied uniforms for 1965?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) No, Sir. Against a total demand of 57,623 garments for the winter of 1964-65, only 1,452 khaki woollen serge garments could not be supplied on account of difficulty in procurement of requisite cloth.

(b) For the requirement of summer 1965 and winter 1965-66, 75 per cent and 50 per cent respectively of the garments have been supplied. The balance could not be supplied due to enormous increase in the number of garments as a result of revised Dress Regulations and standardisation of uniforms based on the recommendations of the Uniforms Committee set up by the Government.

In view of the present emergency and drive for stringent economy, instructions were issued recently to revert to earlier scales if less liberal than the revised scales, as a result of which the uniforms which still remain unsupplied will not now be issued.

SHRI D. THENGARI : How many recommendations of the Uniforms Committee have been implemented so far and how many others are awaiting implementation and may I also know whether on all these zones the implementation is of a uniform pattern?

DR. RAM SUBHAG SINGH : Regarding the exact number of the recommendations which have not been implemented, I require notice. But an effort has been made by all the Railways to implement them as fully as possible, subject to the limitations that I mentioned—virtually by all the Rail-

ways including the Central Railway about which this question has been put. And there is a big figure. If the hon. Member is interested, I will lay it on the Table of the House.

SHRI D. THENGARI : It may kindly be laid on the Table of the House.

My second question is whether in July, 1965 the Administration had issued any directive pertaining to this subject and, if so whether it was in contravention of, or in keeping with, the recommendations of the Uniforms Committee.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That is precisely what I read out that this recommendation which came into effect in 1963 was withdrawn recently due to these economic difficulties.

SHRI D. THENGARI : May I know if these recommendations have not been implemented, in what other ways compensation would be paid to that extent—or relief would be paid—to the affected employees?

DR. RAM SUBHAG SINGH : For the time being, there is no proposal regarding that because one can appear in his own cloth, though not of the category of railway employees. But the moment this economic difficulty is over, we shall consider all these suggestions.

श्री ए०सी० गिलबर्ट : रेलवे कुछ कटेगरी के एम्प्लायीज को हर जोनल रेलवे में दो किस्म के यूनीफार्म देती है, एक गरमी से पहले ठंडा और दूसरा जाड़े से पहले गरम। यह शिकायत है एम्प्लायीज की जो कि बर्दियों के हकदार है कि गर्मियों की यूनीफार्म जब जाड़ा आ जाता है तब मिलती है और जाड़े की यूनीफार्म जब गर्मी आ जाती है तब मिलती है। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इस बात की खबर है कि नहीं? और अगर खबर है तो आपने इस पर क्या कार्यवाही की है? अगर नहीं मालूम है तो मालूम करके आगे देखेंगे कि बर्दिया वक्त पर दी जायेगी।

डा० राम सुभग सिंह : जी हाँ, इस बात का मुझे पता है क्योंकि हम लोग भी रेल पर